Name of the Unit	Whether closed (yes/No)	Examined BIFR (yes /no)
(1) M.P. State Textile Corporation (Sajjan Mills) . . .	Yes	Yes
(2) Binod Mills Co. Ltd.	Yes	Yes
(3) Hope Textiles Ltd.	Yes	Yes
(4) Hukumchand Mill Ltd.	Yes	Yes
(5) Rajkumar Mills Ltd.	No	Yes
(6) D.M. Woollen Mills (P) Ltd.	No	Yes

(c) There has not been any increase in sickness in Textile Industry in Madhya Pradesh nor there has been any report of crisis situation.

(d) Steps taken by Government for increasing production of cloth are not confined to any particular state. However Government have taken following steps for increasing production of cloth and tackle problem of sickness:

1. Liberalisation of Industrial Policy which includes abolishing of License condition for establishment and expansion of units.
2. Setting up of Textile Modernisation Fund Scheme.
3. Permission to Import Textile Machinery as well as major raw materials and reduction in excise/custom duties.
4. Setting up of BIFR/Nodel Agency.
5. Financial institutions and Banks are also required to monitor closely the increase of growing sickness.

उत्तर प्रदेश में जनता कपड़े की बिक्री

418. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश में जनता कपड़े तथा नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े की बिक्री की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों के माध्यम से इन कपड़ों की बिक्री की जा रही है तथा उनका किस्म-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इनकी बिक्री में की जा रही अनियमितताओं की जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

विवरण

(ख) उत्तर प्रदेश में जनता कपड़ा निम्नलिखित वितरण अभिकरणों के विक्रय केन्द्रों के माध्यम से लक्षित उपभोक्ताओं में वितरित किया जा रहा है ।

1. उत्तर प्रदेश उपभोक्ता समिति लि०, लखनऊ ।सहकारी
2. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य और अत्यावश्यक मद्य निगम लि०, कानपुर ।

3. भूतपूर्व सैनिक उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, लखनऊ ।
4. भेलूपुर उपभोक्ता सहकारी भंडार, वाराणसी ।
5. आगरा मंडल विकास निगम, आगरा ।
6. कानपुर थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, कानपुर ।
7. जिला सहकारी संघ, कानपुर ।
8. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ कानपुर ।
9. कानपुर सहकारी क्रय विक्रय समिति, कानपुर ।
10. फतेहपुर सहकारी क्रय-विक्रय समिति, फतेहपुर ।
11. केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, मिर्जापुर
12. उत्तर प्रदेश पुलिस, कानपुर ।
13. इलाहाबाद मंडल विकास निगम, इलाहाबाद ।

उपरोक्त अभिकरणों के अतिरिक्त राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों जैसे :— उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर और उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, कानपुर को अपने कुल जनता कपड़े के उत्पादन का अधिकतम 15% तक अपने खुदरा शोरूम के माध्यम से विक्रय करने की भी अनुमति दी जाती है । इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा धोती, रंगीन/छपी हुई साड़ियां, कमीज का कपड़ा, लंबा कपड़ा, शॉडी, कंबल और ऊनी शॉल उत्पादित किए जाते हैं । राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा उत्पादित कंट्रोल साड़ी, धोती, लंबा कपड़ा, तथा कमीज का कपड़ा, एन०सी सी०एफ०, उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य और आवश्यक वस्तु निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के खुदरा विक्रय केंद्र और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्राधिकृत डीलर के माध्यम से बेचा जाता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारत सरकार ने जनता कपड़े के वितरण व अन्य इसी प्रकार की बातों के विनियमन के लिए संशोधित मार्गदर्शिका जारी की है जिसमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए राज्य प्राधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे और वितरण के समस्त पहलुओं की देख-रेख राज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी । यह समिति वितरण व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा भी करती है ।

चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

4119. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत तथा अधीनस्थ कार्यालयों में गठित की गई चयन समितियों/बोर्डों में नियुक्त किये गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों के नाम तथा पदनाम क्या-क्या है;

(ख) क्या कुछ निकाय ऐसे भी है जहां ये स्थान रिक्त है;

(ग) यदि हां, तो कब से तथा उनका कारणों सहित ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) सरकार के निदेशानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्प संख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों को चयन समितियों में नामित किया जाना अपेक्षित है । तथापि विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी० सी०) के शो रूम

4120. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कुल कितने शो रूम हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थित हैं ; और